also monitored by Ministry of Planning and Programme Implementation. A task force under the Chairmanship of the Secretary, Planning Commission has also been constituted to expedite the completion of the projects in power and coal sectors. The Committee of Secretaries has also been reviewing the progress of these projects from time to time to resolve the problems faced by them.

1741. [*Transferred to the 13th March, 1992*].

क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए जारी किए गए निदेश

1742. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने योजना आयोग को क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं और सामाजिक दमन को कम करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में समस्त देश के खनिज भण्डारों के कितने प्रतिशत खनिज भण्डार हैं, प्रमुख खनिजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और विभिन्न योजनाओं द्वारा उनके समुचित उपयोग के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितना खर्च आने की संभावना है और बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के राज्यों पर कुल खर्च में से प्रत्येक राज्य पर कितने-कितने प्रतिशत खर्च किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार गाडगिल फार्मूले को रद्द करने का विचार कर रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलनों में कमी तथा सामाजिक दबाव किसी हद तक सरकार तथा योजना आयोग की आयोजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

(ख) सभी राज्यों में खनिज-वार भण्डारों का अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक राज्य में काफी संख्या में बड़े और छोटे खनिज हैं जो सम्भावना और महत्ता में अलग-अलग होते हैं और अतः राज्य का अंशदान सामान्यतः खनिज उत्पादन के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है जैसाकि भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका (आईएमवाईबी) में दर्शाया गया है।

बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों का अंशदान (परमाणु खनिजों को छोड़कर) नीचे दिया है जैसाकि 1988 में खनिज उत्पादन के मूल्य पर आधारित भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका 1991 में दर्शाया गया है :—

राज्य	खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ रु० में)	प्रतिशत अंशदान
भारत	14272	100
बिहार	2057	14.41
पश्चिम बंगाल	706	4.95
मध्य प्रदेश	1493	10.47
उड़ीसा	468	3.28

राज्यवार महत्वपूर्ण खनिजों के ब्यौरे निम्न है :

(मिलियन टन में)

खनिज	रिजर्व	
बिहार		
(1) बाक्साइट	63.52	1-1-85 के अनुसार
(2) चाइना मृत्तिका	41.79	1-1-85 के अनुसार
(3) तांबा अयस्क	154.19	-वही-
(4) डोलोमाइट	20.65	-वही-
(5) फायर मृत्तिका	47.87	वही-
(6) लौह अयस्क (हेमेटाइट)	3083.25	-वही-
(7) क्येनीट	0.15	-वही-
(8) चूनापत्थर	572.90	-वही-
(9) कोयला	61155.11	-वही-
पश्चिम बंगाल		
(1) एपेटाइट	1.53	1-1-85 के अनुसार
(2) चाइना मृत्तिका	249.72	-वही-
(3) डोलोमाइट	314.09	-वही-
(4) फायर मृत्तिका	6.49	-वही-
(5) चूनापत्थर	27.06	वही
कोयला	29903.87	1-1-90 के अनुसार
मध्य प्रदेश		
(1) बाक्साइट	126.80	1-1-85 के अनुसार
(2) मृत्तिका	17.95	-वही-
(3) तांबा अयस्क	84.83	-वही-
(4) डोलोमाइट	1638.10	-वही-
(5) लौह अयस्क	2186.22	-वही-
(6) चूनापत्थर	8011.42	-वही-
(7) मैंगनीज अयस्क	19.69	-वही-
(8) कोयला	32649.93	1-1-90 के अनुसार
उड़ीसा		
(1) बाक्साइट	1370.45	1-1-85 के अनुसार
(2) क्रोमाइट	51.56	-वही-

(मिलियन टन में)

खनिज	रिजर्व	
(3) डोलोमाइट	562.63	1-1-85 के अनुसार
(4) फायर मृत्तिका	88.42	-वही-
(5) ग्रेफाइट	0.60	-वही-
(6) लौह अयस्क	2602.34	-वही-
(7) चूनापत्थर	1017.38	-वही-
(8) मैंगनीज अयस्क	33.58	-वही-
(9) टीटानीफेरस मेगनेटाइट	2.17	-वही-
(10) क्वार्टजीट	7.13	-वही-
(11) कोयला	44261.54	1-1-90 के अनुसार

मुख्यत: केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सीआईएल, एसएआईएल, एम ओआईएल, एचसीएल आदि को केप्टिव खानों में कोयला, चूना, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क तथा तांबा आदि का दोहन किया जा रहा है। राज्य संगठन का वैजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा निजी क्षेत्रक भी खनिजों मुख्यत: औद्योगिक/गैर-धातु खनिजों के उत्पादन में लगे हुए हैं। खनिजों के विकास तथा संदोहन के लिए कई स्कीमें पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं में शुरू की गई हैं। इनके आठवीं योजना, जिसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, में जारी रखने की सम्भावना है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर, 1991 में हुई अपनी 43वीं बैठक में राज्यों को केन्द्रीय सहायता वितरण के लिए गाडगिल फार्मूला नाम से जाने वाले फार्मूले के संशोधित स्वरूप का अनुमोदन कर दिया है।

Export and Import as Percentage of G.N.P.

1743. SHRIMATI MIRA DAS: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what is the plan target for the current and next year for exports and imports and what percentage it forms of our G.N.P.; and

(b) whether it is a fact that 13 per cent exports of GNP are planned at the end of Eighth Plan; if so, what are the ways of achieving this target?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) Year-wise targets for exports and imports are not fixed as a part of the plan. For the Eighth Five Year Plan, the target for export growth has been indicated as 13.6 per cent per annum on an average. Details of steps for achieving the target will be available after the Eighth Plan Document is finalised.

Protection of Handlooms from Competition from Powerlooms

1744. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government policy is to protect handloom weavers from unequal competition from mills and powerlooms;

(b) if so, whether Government's attention has been drawn to Tamil Nadu Government's decision to convert handlooms into powerlooms with NABARD;

(c) whether Government are aware that such steps would lead to the unemployment of lakhs of handloom weavers; and